उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 10 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–07(10/68)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन एक कर्मयोगी लोकनायक थे। जिन्होंने अपने आदर्श जीवन दर्शन से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया तथा समाज को नई दिशा दी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

नई टिहरी/देहरादून 10 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–06(10/67)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को रामलीला मैदान नरेन्द्रनगर में 43वें सिद्धपीठ मॉ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला–2018 का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सिंचाई विभाग की 12 करोड 16 लाख रूपये की योजनाओं का लोकार्पण तथा लोक निर्माण विभाग की 9 करोड़ 84 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पण की गई योजनाओं में जनपद टिहरी गढ़वाल में चन्द्रभागा नदी के बायें तट पर ढ़ालवाला पुल से चन्द्रभागा पुल तक सुदृढ़िकरण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल है। शिलान्यास की गई योजनाओं में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्गेनिक फॉमिंग एवं टिहरी भवन एवं विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में डाबरखाल भैस्यारों मोटरमार्ग का सुधारीकरण/डामरीकरण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों एवं स्कूली छात्र–छात्राओं द्वारा निकाली गई झांकियों का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी को नवरात्रों की बधाई देते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास राज्यहित से जुड़ा है। हमारी सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखण्ड की भौगोलिक विशिष्टताओं को देश व दुनिया के सामने रखा। इस कारण दुनियाभर के निवेशक उत्तराखण्ड की ओर आकर्षित हुए है। उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखण्ड के लिये ऐसी नीतियां बनानी होगी जो युवाओं के भविष्य को संवारे। हमें राज्य के युवाओं को व्यवसायी बनाना है, ताकि वे दूसरों को भी रोजगार दे सकें। हमारे प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। इनका सदुपयोग कैसे हो, यह सोच विकसित करनी होगी। हमें 2025 तक प्रदेश में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किये है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल के अनुरोध पर क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न घोषणाएं भी की जिनमें राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्रनगर को पीजी कॉलेज का दर्जा दिये जाने, नरेन्द्रनगर विकासखण्ड के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त ढ़ालवाला ड्रेन सड़क की मरम्मत कार्य, नरेन्द्र विकासखण्ड के तपोवन क्षेत्र में लक्ष्मण झूला के डाउन स्ट्रीम सच्चा धाम घाट(गऊ घाट) के निर्माण किये जाने, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गजा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकरण, तपोवन की विभिन्न सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य, गूलर–सालब–भगवा सेरा मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने, नरेन्द्रनगर–डागर–सोनी फर्त मोटर मार्ग का डामरीकरण, गौंताचली–घंटाकरण मोटरमार्ग, द्वितीय चरण निर्माण पूरा किये जाने, अदवाणी बेसी मोटर मार्ग का पोखरी तक विस्तार किये जोन, ओडांडा–पसर–डांडा मोटर मार्ग का द्वितीय चरण का कार्य पूरा किये जाने, हिडोला–मुडाला मोटर मार्ग का नव निर्माण, कारगिल शहीद जगत सिंह मोटर मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ना, संसमण–कौडियाला मोटर मार्ग का अवशेष निर्माण कार्य पूरा किये जाने, सत्या डांडा–पल्या डांडा–कसमोली मोटरमार्ग का नव निर्माण किये जाने, तैला–कोटेश्वर मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने एवं सौरपानी–चमराडा देवी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने की घोषणा की।

कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कुंजापुरी मेले के इतिहास पर प्रकाश डाला तथा जनपद के विकास हेतु विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर विधायक श्री शक्तिलाल शाह, पूर्व विधायक श्री ओम गोपाल रावत, ब्लॉक प्रमुख सुश्री बिनीता बिष्ट, जिलाधिकारी सुश्री सोनिका, एस.एस.पी. श्री योगेन्द्र सिंह रावत, मुख्य विकास अधिकारी श्री आशीष भटगांई, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री संजय नेगी आदि उपस्थित थे।

नोट : जिला सूचना कार्यालय नई टिहरी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर ।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 10 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–05(10/66)**

केन्द्रीय वस्त्र राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा सांसद एवं श्री भगत सिंह कोश्यारी ने बुधवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से भेंट कर टनकपुर–बागेश्वर रेल लाइन के शीघ्र निर्माण का अनुरोध किया है। इस संबंध में रेल मंत्री को लिखे पत्र में श्री टम्टा ने कहा है कि उनके संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा की जनता कई दशकों से टनकपुर–बागेश्वर रेल मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर संघर्षरत है। इस रेल मार्ग के निर्माण हेतु 1912 में ब्रिटिश शासनकाल से वर्ष 2010–11 तक अनेक बार सर्वे का कार्य किया गया है। उन्होंने इस विषय को लोकसभा में रेल बजट पर अपने भाषण में भी उठाया था और इसका निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा की याचिका समिति के समक्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा टनकपुर–बागेश्वर रेलमार्ग को भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में चिन्हित किया था। समिति द्वारा अपनी 141वीं रिपोर्ट में इसके शीघ्र निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। इस रेल मार्ग के निर्माण में विलम्ब से क्षेत्रवासियों में अत्यंत रोष है। उन्होंने इस संबंध में बागेश्वर–टनकपुर रेलमार्ग निर्माण संघर्ष समिति के साथ सांसद श्री भगत सिंह कोश्यारी के पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें भी उल्लेख किया गया है कि सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से संसद की याचिका समिति के सम्मुख हिमालयी राज्यों में 14 नये रेल लाईनों की आवश्यकता बताई गयी। इन 14 रेल लाईनों में तीन उत्तराखण्ड से है जिनमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग चमोली, टनकपुर–बागेश्वर व टनकपुर–जौलजीवी है। इनमें टनकपुर बागेश्वर रेल लाईन के बीच में लगभग 80 किमी के बाद जौलजीवी 35 किमी के आसपास रेल लाईन बनेगी। उक्त रेल लाईनों में टनकपुर–बागेश्वर–जौलजीवी छोडकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग सहित सभी रेल लाईनों को केन्द्र ने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में ले लिया है।

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय सुरक्षा व सीमान्त क्षेत्र की जनता के हित में टनकपुर–बागेश्वर रेल लाईन को शीघ्र बनवाने का कष्ट करें। सामरिक महत्व के कारण इसे नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा सकता है। इस रेल लाईन के बनने से भारत के साथ–साथ नेपाल के नागरिकों को भी बहुत सुविधा होगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 10 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(10/65)**

सचिवालय सभागार में अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उप योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह ने समस्त सचिव एवं विभागाध्यक्षों को योजनाओं की वित्तीय प्रगति के साथ–साथ भौतिक प्रगति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हर माह की 05 तारीख को प्रत्येक दशा में मासिक प्रगति रिपोर्ट अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव डॉ0 रणवीर सिंह ने यथा दुग्ध विकास, लघु सिंचाई, सिंचाई, ऊर्जा, उरेडा, परिवहन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, युवा कल्याण, ऐलौपैथिक, ग्राम्य विकास, पेयजल, आई.सी.डी.एस तथा सेवायोजन विभाग द्वारा माह अक्टूबर की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध न कराने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग द्वारा बजट का शत प्रतिशत उपयोग सम्भव न हो तो वे संबंधित सूचना अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध करा दें।

ज्ञातव्य है कि अनुसूचित जाति उप योजना में 2018–19 में 1460.96 करोड़ रूपए का प्राविधान है। जिसके सापेक्ष अब तक विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं में 563.72 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष सितम्बर माह तक 175.51 करोड़ रूपए व्यय किया जा चुका है। जबकि अनुसूचित जनजाति उप योजना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में 477.03 करोड़ का प्राविधान है जिसके सापेक्ष 204.52 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है तथा सितम्बर माह तक 70.57 करोड़ रूपया उपयोग किया जा चुका है।

इस अवसर पर अपर सचिव समाज कल्याण श्री राम बिलास यादव, निदेशक पंचायत श्री हरि चन्द्र सेमवाल, अपर सचिव डॉ. धीरेन्द्र सिंह दत्ताल, अपर सचिव सिंचाई श्री देवेन्द्र पालीवाल, अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ के अधिकारी श्री जी0आर.नौटियाल समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

देहरादून 10 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(10/64)**

निदेशक उद्योग श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत औद्योगिक विकास योजना–2017 राज्य के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् स्थापित होने वाली नई ईकाइयाँ एवं विद्यमान इकाइयों के विस्तारीकरण संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये अचल पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत, अधिकतम 05 करोड़ रुपये की केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन तथा केन्द्रीय व्यापक बीमा राजसहायता योजनान्तर्गत भवन तथा संयंत्र के बीमा प्रिमियम पर 05 वर्ष के लिए शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि योजना की अधिसूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2017 अथवा इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों को दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक योजनान्तर्गत ऑन लाईन पंजीकरण करना अनिवार्य था। अब भारत सरकार द्वारा ऑन लाईन पंजीकरण की अवधि को दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक बढ़ा दी गई है। ऐसी सभी इकाइयाँ, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे इकाइयाँ दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक डी.आई.पी.पी., वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल पर अपनी इकाई का पंजीकरण करा सकते हैं।

इस संबंध में आवश्यक जानकारी डी.आई.पी.पी., वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

रूद्रप्रयाग/देहरादून 10 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(10/64)**

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह व पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने हैलीकाप्टर से केदारधाम में पहुंचकर धाम में निर्माणधीन रेप्लिका, रास्ते, उद्धव कुण्ड व आदि कार्यों का निरीक्षण कर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को ससमय कार्य पूर्ण करने के साथ ही आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार ने सिंचाई विभाग को 31 अक्टूबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को एम.आई–26 से मन्दिर तक स्थित विद्युत पोलों से लटकती हुई पुरानी तारों को परिस्थिति अनुसार बदलने या भूमिगत करने के निर्देश दिए। निम को केदारपुरी में वायरकेट को आर्कषित व रमणीय बनाने हेतु प्रोटोक्षन वाल या हल्का स्लोप देने, डीडीएमए को बायोमैट्रिक के सामने बन रहे हाट बाजार के कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए जिससे व्यवसायियों की समस्याओं का निस्तारण ससमय हो सके। इसके साथ ही हाट बाजार में बन रही दुकानों के बीच एक समान अन्तर रखने, दुकानों के आगे स्थित जगह पर कन्क्रीट के स्थान पर मखमली घास उगाने, रूद्रा प्वांइट से केदारपुरी तक स्थित समस्त साइन बोर्डो को हटाने, मंदाकिनी नदी के पार पुराने घोडा पड़ाव पर स्थित पुराने बीकेटीसी के स्ट्रकचर को हटाने, कावरा हाउस पर टिन के 03 अवैध अतिक्रमण को हटाने, उद्धव कुण्ड को खुला रखने, वीआईपी हैलीपैड से मन्दिर तक रास्ते की मरम्मत करने व आदि निर्देश दिए।

केदारधाम में मन्दाकिनी घाट से मन्दिर दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को लम्बी कतार व श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घूम कर न आना पडे इसके लिए मन्दिर के आगे स्थित रैप्लिका से सीधा रास्ता बनाने के निर्देश निर्माणदायी संस्था को दिए। मन्दिर में स्वच्छता पर विशेष जोर देने, चबूतरे के सामने खाली पडी जगह पर मैट लगाने के भी निर्देश दिए। जिससे कि पूरी केदारपुरी आकर्षण व मनमोहक बनी रहे।

इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री मंगेष घिल्डियाल ने समस्त विभागों को मुख्य सचिव द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि समयान्तर्गत विभाग कार्य पूरा करे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी श्री गोपाल सिंह चौहान, निम से श्री मनोज सेमवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

चमोली/देहरादून 10 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(10/63)**

श्री बद्रीनाथ धाम को भवष्यि में मास्टर प्लान के तहत विकसित करने को लेकर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह एवं पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने बद्रीनाथ धाम में शासन स्तर से हायर कम्पनी के कन्सलटेंट के साथ प्रस्तावित मास्टर प्लान का अवलोकन करते हुए उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ धाम को मास्टर प्लान के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की है। इसी तर्ज पर अब श्री बद्रीनाथ धाम को भी मास्टर प्लान के तहत विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने कहा विगत वर्षो की अपेक्षा इस बार तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की सख्यां बढी है। कहा कि आगामी समय में ऑलवेदर रोड़ एवं रेल परियोजना का कार्य पूरा होने पर बद्रीनाथ धाम में प्रतिवर्ष रिकार्ड यात्रियों की पहुॅचने की सम्भावना है। भविष्य को लेकर श्री बद्रीनाथ धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने की योजना है। मुख्य सचिव एवं पर्यटन सचिव ने कन्सलटेंट के साथ प्रस्तावित मास्टर प्लान के बारे में बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर धाम में संचालित एवं प्रस्तावित कार्यो की जानकारी भी ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बद्रीनाथ में प्रस्तावित एवं संचालित कार्यो का डाटा कन्सलटेंट के साथ शेयर करने के निर्देश दिये। ताकि फाइनल मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यो को भी शामिल किया जा सके।

पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि राज्य में हैलीकॉप्टर कनेक्टिविटी अच्छी होने से धाम पहुॅचने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही सड़क सुविधाऐं विकसित होने पर भविष्य में पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 15–20 सालों में पर्यटकों को अच्छी सुविधाऐं मुहैया हो सके, उसके हिसाब से टाऊन की प्लानिंग की जा रही है। कहा कि मुख्य सचिव के निर्देशन में इसका खाका तैयार करते हुए आगे की कार्यवाही की जायेगी जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जायेगा।

मुख्य सचिव एवं पर्यटन सचिव ने अंतिम गांव माणा का भी भ्रमण कर प्रस्तावित कार्यो के संबध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि माणा गांव के प्रसिद्ध हस्तशिल्प को आगे बढाने के लिए शासन स्तर से ठोस योजना संचालित करने का प्रयास किया जायेगा। जिससे यहॉ के काश्तकारों को इसका पूरा फायदा मिल सके। इससे पूर्व मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह एवं पर्यटन सचिव ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की।

इस दौरान जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी श्री हसांदत्त पांडे, ईई लोनिवि श्री डीएस रावत, जिला पर्यटन विकास अधिकारी श्री बिजेन्द्र पांडे सहित जल संस्थान, जल निगम, विद्युत, उरेडा, लघु सिंचाई, वन, नगर पंचायत आदि विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग